

रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

“रेल है राष्ट्र की जीवनधारा, जोड़े हर दिल, हर बस्ती, हर किनारा।”

“चलती रेल है प्रगति की पहचान, साथ लेकर चलती है पूरा हिंदुस्तान।”

वर्ष-35 अंक:14 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 16-31 जुलाई 2025 पृष्ठ 08 मूल्य:20 रु. मात्र + डाक खर्च (रंगीन सहित)

अब ट्रेन में हर गतिविधि पर रहेगी नजर : यात्रियों की सुरक्षा के लिए डिब्बों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

बेहतर सुरक्षा के लिए सभी 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजन में सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक डिब्बे में 4 सीसीटीवी कैमरे और लोकोमोटिव में 6 कैमरे लगाएगा रेलवे

सूत्र/रे.स.ब्यू- यात्री डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रायोगिक परिणाम के सकारात्मक परिणाम के आधार पर, रेलवे ने सभी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम से यात्री सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। बदमाश और संगठित गिरोह भोले-भाले यात्रियों का फायदा उठाते हैं। कैमरे लगने से ऐसी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी। यात्रियों की निजता बनाए रखने के लिए, दरवाजों के पास सामान्य आवागमन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इंजनों और डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रगति की समीक्षा की। शनिवार 12 जुलाई, 2025 को आयोजित बैठक में रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

360-डिग्री व्यापक कवरेज- रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तर रेलवे के लोको इंजन और डिब्बों में सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने सभी 74,000 डिब्बों और 15,000 इंजनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति दे दी है। प्रत्येक रेलवे डिब्बे में 4 डोम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे - प्रत्येक प्रवेश मार्ग पर 2 और प्रत्येक लोकोमोटिव में 6 सीसीटीवी



कैमरे होंगे। इनमें लोकोमोटिव के आगे, पीछे और दोनों तरफ 1-1 कैमरा शामिल होंगे। प्रत्येक कैब (आगे और पीछे) में 1 डोम सीसीटीवी कैमरा और डेस्क पर 2 माइक्रोफोन लगाए जाएंगे।

आधुनिक समस्याओं के लिए आधुनिक निगरानी- अधिकारियों ने साझा किया कि सीसीटीवी कैमरे नवीनतम मानकों वाले होंगे और एसटीक्यूसी प्रमाणित होंगे। केंद्रीय रेल मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ उपकरणों को इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे



अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि 100 किमी प्रति घंटे से अधिक गति और कम रोशनी की स्थिति में चलने वाली ट्रेनों के उच्च गुणवत्ता वाले फुटेज उपलब्ध हों। केंद्रीय रेल मंत्री ने अधिकारियों को इंडियाएआई मिशन के सहयोग से सीसीटीवी कैमरों द्वारा लिए गए डेटा पर एआई के उपयोग का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

डेटा गोपनीयता - डिब्बों के सामान्य आवागमन क्षेत्रों में कैमरे लगाने का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार लाना है। निजता का ध्यान रखते हुए, ये कैमरे शरारती तत्वों की पहचान करने में भी मदद करेंगे। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के प्रयास, सुरक्षित, संरक्षित और यात्री-अनुकूल यात्रा अनुभव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्पूरीग्राम को दी विकास की सौगात: ₹17.30 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, दीघा ब्रिज हॉल्ट का निरीक्षण

रेल बजट, जो बिहार के लिए पहले मात्र ₹1,000 करोड़ था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़कर ₹10,000 करोड़ हो गया है : अश्विनी वैष्णव



सूत्र/रे.स.ब्यू- केंद्र सरकार द्वारा बिहार की रेलवे संरचना को आधुनिक और सुविधा-सम्पन्न बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार में रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के कैबिनेट मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के समस्तीपुर मंडल स्थित कर्पूरीग्राम स्टेशन परिसर में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सबसे पहले दीघा ब्रिज हॉल्ट का निरीक्षण कर वहां यात्री सुविधा, संरक्षा, साफ-सफाई, प्लेटफॉर्म की स्थिति, पेयजल, रोशनी एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी यात्रियों को आधुनिक और सुरक्षित रेल अनुभव प्रदान करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके उपरान्त रेल मंत्री ने कर्पूरीग्राम स्टेशन परिसर में ₹3.30 करोड़

की लागत से होने वाले स्टेशन उन्नयन कार्यों का शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत स्टेशन भवन का आधुनिकीकरण, प्रतीक्षालय, शौचालय, डिजिटल सूचना प्रणाली, पेयजल सुविधा, दिव्यांगजनों के लिए रैम्प एवं अन्य यात्री सुविधा कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कर्पूरीग्राम स्टेशन पर यात्री सुविधा से जुड़ी कई नवनिर्मित सुविधाओं का उद्घाटन भी किया। रेल मंत्री श्री वैष्णव ने इसके पश्चात कर्पूरीग्राम और खुदीराम बोस पूसा स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक संख्या 59 'C' पर ₹14.0 करोड़ की लागत से बनने वाले अंडरग्राउंड रेलवे सब-वे के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि यह अंडरग्राउंड रेलवे सब-वे के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद स्थानीय वाहन



यातायात को बड़ी राहत देगा और ट्रेनों की सुचारु आवाजाही में भी मदद मिलेगी, जिससे संरक्षा में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा 33,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में कई गुना अधिक है। यह कार्य न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देता है। रेल मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार बिहार जैसे राज्यों को 'विकसित भारत' की परिकल्पना में भागीदार बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर राज्य मंत्री (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) श्री रामनाथ ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी, और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की उपस्थिति रही।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 नौकरियां देने की योजना, रेल मंत्रालय ने दी जानकारी

**2024 से 1.08 लाख रिक्रियों की घोषणा की गई:
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 नियुक्तियां की जाएंगी**

सूत्र/रे.स.ब्यू. रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने नवंबर 2024 से अब तक 55197 रिक्रियों वाली सात विभिन्न अधिसूचनाओं के लिए 1.86 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) आयोजित की हैं। इससे आर-आरबी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान कर सकेगा।

इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में आरआरबी द्वारा 9000 से अधिक नियुक्तियों की जा चुकी हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसमें काफी योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। आरआरबी ने हाल ही में अभ्यर्थियों के निवास स्थान के नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटित करने की पहल की है, जिसमें महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

इसके लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिक परीक्षा केंद्रों को सूचीबद्ध करने और अधिक मानव संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। आरआरबी द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 2024 से 108324 रिक्रियों के लिए बारह अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं, अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 से अधिक नियुक्तियों की जाएंगी। परीक्षा की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पहचान प्रमाणित करने के लिए ई-केवाईसी आधारित आधार प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया है। इससे पहचान प्रमाणित करने में 95 प्रतिशत से अधिक सफलता मिली। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल करने की गुंजाइश को खत्म करने के लिए अब आरआरबी के सभी परीक्षा केंद्रों पर शत-प्रतिशत जैमर लगाए जा रहे हैं।

निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अभ्यर्थियों के प्रमाणीकरण के लिए आधार का उपयोग कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से नकल करने की गुंजाइश को खत्म करने के लिए जैमर का उपयोग कर रहा है।

चार्टिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव: पहले आरक्षण चार्ट अब ट्रेन स्वाना होने से 8 घंटे पहले जारी, पहले से जान सकेंगे अपनी सीट की स्थिति।

सूत्र/रे.स.ब्यू. यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और उन्हें अपनी यात्रा की बेहतर तरीके से योजना बनाने में मदद करने के लिए, रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के आरक्षण चार्ट तैयार करने और जारी करने के समय में संशोधन करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में आरक्षित यात्रियों के नाम, कोच और बर्थ विवरण की जानकारी वाले आरक्षण चार्ट प्रारंभिक स्टेशन या दूरस्थ स्थान स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले तैयार और जारी किए जाते हैं। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, दिनांक 10.07.2025 से, ट्रेन का पहला आरक्षण चार्ट अब ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 8 घंटे पहले (पहले 4 घंटे के बजाय) तैयार किया जाएगा।

संशोधित चार्टिंग समय के अनुसार:

- 05:00 बजे से 14:00 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, पहला आरक्षण

चार्ट पिछले दिन 21:00 बजे तक तैयार किया जाएगा।

- 14:00 बजे से 05:00 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।
 - दूसरे आरक्षण चार्ट के लिए मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, जो मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगा।
 - अंतिम आरक्षण चार्ट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तैयार किया जाना जारी रहेगा।
- यात्री अंतिम चार्ट तैयार होने से पहले खाली बर्थ बुक कर सकेंगे। इस कदम से यात्री अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे और बोर्डिंग स्टेशनों तक पहुंचने के लिए अंतिम घंटों की भीड़ से बच सकेंगे, जिससे कर्मचारियों और यात्रियों दोनों को लाभ होगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में 'क्विक कोच वाटरिंग सिस्टम' की स्थापना से यात्रियों को मिल रही बेहतर सुविधा

सूत्र/रे.स.ब्यू. यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में रेलवे लगातार नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में, ट्रेनों के कोचों में पानी की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए 'क्विक कोच वाटरिंग सिस्टम' की स्थापना की जा रही है। यह प्रणाली गाड़ियों में कम समय में पानी भरने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे संचालन में दक्षता और यात्रियों की संतुष्टि दोनों में वृद्धि होती है। पूर्वोत्तर रेलवे के ऐशबाग, गोरखपुर जंक्शन, बनारस, छपरा, मऊ जंक्शन, फर्रुखाबाद, कासगंज और लालकुआं स्टेशनों पर यह सिस्टम पहले ही स्थापित किया जा चुका है। सीतापुर और बलिया में कार्य प्रगति पर है। यह तकनीक 55 लीटर प्रति सेकंड की गति से पानी भरने की क्षमता रखती है, जिससे पूरे रैक को बेहद कम समय में भरना संभव हो जाता है। इसके माध्यम से रीयल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे पानी की उपलब्धता, दबाव, प्रवाह और खपत की जानकारी स्क्रीन पर तुरंत देखी जा सकती है। यह प्रणाली मोबाइल एसएमएस के जरिए भी संचालित की जा सकती है और मैन्युअल मोड में भी कार्य कर सकती है।

प्रमुख लाभ:

- **तेजी से जल भराव:** 55 लीटर/सेकंड की गति से कम समय में कोचों में पानी भरना संभव।
- **समय की बचत:** ट्रेनों के ठहराव की अवधि नहीं बढ़ती, समयबद्ध संचालन में मदद।
- **पानी की बर्बादी में कमी:** निर्धारित प्रवाह व नियंत्रण प्रणाली के कारण जल संरक्षण।
- **रियल टाइम मॉनिटरिंग:** एक स्क्रीन पर प्रेशर, फ्लो, खपत आदि का लाइव डाटा उपलब्ध।
- **मोबाइल से नियंत्रण:** एसएमएस के जरिए भी सिस्टम को किया जा सकता है संचालित।
- **कम रखरखाव:** मैन्युअल व ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों के साथ, पर्यावरण अनुकूल तकनीक।
- **मानव श्रम की बचत:** श्रमिकों पर भार कम, संचालन अधिक कुशल।

रेलवे की यह पहल यात्रियों के लिए जल सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी प्रगति है, जो समय, संसाधन और पर्यावरण-तीनों के संरक्षण की दिशा में भी सहायक है।

आईआरसीटीसी की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से पुरी, कोलकाता, गंगासागर यात्रा करने का सुनहरा मौका

सूत्र/रे.स.ब्यू. इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईआरसीटीसी भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। आईआरसीटीसी को स्टेशनों, ट्रेनों पर खानपान और आतिथ्य सेवाओं को उन्नत करने एवं पेशेवर बनाने और प्रबंधित करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे की एक विस्तारित शाखा के रूप में स्थापित किया गया है। इसी क्रम में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, वाया-गया, पुरी जगन्नाथ, कोणार्क मंदिर, कोलकाता, गंगासागर, बैजनाथ धाम, वाराणसी, अयोध्या की यात्रा का संचालन किया जा रहा है।

इस यात्रा के मुख्य आकर्षण निम्नवत हैं:

- **यात्रा गंतव्य-** विष्णुपद मंदिर (गया), पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर (उड़ीसा), कोलकाता, गंगासागर, बैजनाथ धाम (जसीडीह), काशी विश्वनाथ मंदिर (वाराणसी), राम मंदिर, हनुमानगढ़ी सरयू आरती (अयोध्या)।
- श्रेणी अनुसार कुल बर्थों की सं० 767& 02 एसी (कुल 49 सीटें), 03 एसी (कुल

70 सीटें) एवं स्लीपर (कुल 648 सीटें)

- **उतरने/चढ़ने के स्टेशन-** आगरा कैंट - ग्वालियर - वीरांगना लक्ष्मी बाई झॉंसी - उरई - कानपुर - लखनऊ - अयोध्या - वाराणसी।

- **यात्रा तिथि-** दिनांक 13-09-2025 से 22-09-2025 तक 09 रात एवं 10 दिन।

इस पैकेज में 02 एसी, 03 एसी एवं स्लीपर क्लास यात्रा, नाश्ता एवं दोपहर व रात्रि का शाकाहारी भोजन, एसी/ नॉन एसी बसों द्वारा स्थानीय भ्रमण सम्मिलित है। इकोनामी श्रेणी (स्लीपर क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रु०- 18460/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रु०- 17330/- है। (स्लीपर क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर नॉन एसी होटलों में ठहरने) नॉन एसी होटल के कमरे में मल्टी शेयर पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था) स्टैंडर्ड श्रेणी (3एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रु०- 30480/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रु०- 29150/- है। (3एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, नॉन एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन

शेयरिंग-पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था) कम्फर्ट श्रेणी (2एसी क्लास) में ठहरने पर पैकेज का मूल्य रु०- 40300/- प्रति व्यक्ति एवं प्रति बच्चे (5-11 वर्ष) का पैकेज का मूल्य रु०- 38700/- है। (2एसी क्लास ट्रेन यात्रा, डबल/ट्रिपल पर एसी होटलों में ठहरने, एसी होटल के कमरे में डबल/ट्रिपल पर (शेयरिंग/नॉन शेयरिंग- पैकेज के अनुसार) वॉश एंड चेंज एवं एसी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था)। इस यात्रा सेवा में LTC एवं EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। ईएमआई की सुविधा आईआरसीटीसी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है। इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जायेगी। उक्त यात्रा की बुकिंग हेतु पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctctourism.com से आनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है।

अधिक जानकारी एवं बुकिंग के लिये नीचे दिये गये मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं:
9236391908, 8287930908, 8595924300, 9305111763, 8595924294, 8595924299, 8287930926 - 8595924293,

प्रयागराज मण्डल में चला मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान, 4 लाख रुपये से अधिक वसूला गया जुर्माना

683 यात्रियों को किया गया प्रभारित , 6 अवैध वैंडरों को भेजा गया जेल

सूत्र/रे.स.ब्यू. रेल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं नियमबद्ध यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयागराज मण्डल द्वारा जून माह में ट्रेनों एवं स्टेशनों पर विशेष सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री हिमांशु शुक्ला के निर्देशानुसार संचालित किया गया। इसका उद्देश्य बिना टिकट एवं अनियमित टिकट यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए यात्रियों को नियमबद्ध और वैध टिकट के साथ यात्रा के प्रति जागरूक करना था। प्रयागराज मण्डल में दिनांक 06-07-2025 को प्रयागराज जंक्शन पर, 11-07-2025 को मिर्जापुर में एवं 13-07-2025 को प्रयागराज छिवकी में बिना टीकट, अनियमित टिकट, बिना बुक किए गए समाग, गंदगी फैलाने वालों एवं अवैध वैंडरों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस अभियान में 24 अवैध वैंडरों को पकड़ अग्रिम कार्यवाई हेतु रेलवे सुरक्षा बल के सुपुर्द किया गया, मजिस्ट्रेट कार्यवाई के उपरांत इनमें से 6 अवैध वैंडरों को जेल भेज दिया गया। प्रयागराज जंक्शन पर चलाये गए मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान में वाणिज्य विभाग के 15 टिकट चेकिंग स्टाफ ने रेलवे सुरक्षा बल व

चेकिंग स्टाफ ने रेलवे सुरक्षा बल व राजकीय रेलवे पुलिस के 15 कर्मचारियों के सहयोग से अभियान चलाया। इस अभियान में 15 गाड़ियों को चेक कर 340 यात्रियों से 2,30,620/- रुपये वसूले गए। इसमें 142 यात्रियों से बिना टिकट यात्रा के लिए 1,38,180/- रुपये जुर्माना वसूला गया, 196 यात्रियों से अनियमित टिकट पर यात्रा के लिए 91,840/- रुपये जुर्माना वसूला गया एवं 2 यात्रियों से गंदगी फैलाने के लिए के लिए 600/- रुपये जुर्माना वसूला गया। इस अभियान में 6 अवैध वैंडरों को पकड़कर हेतु रेलवे सुरक्षा बल के सुपुर्द किया गया। मिर्जापुर स्टेशन पर चलाये गए मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान में वाणिज्य विभाग के 7 टिकट चेकिंग स्टाफ ने रेलवे सुरक्षा बल व राजकीय रेलवे पुलिस के 7 कर्मचारियों के सहयोग से अभियान चलाया। इस अभियान में 6 गाड़ियों को चेक किया गया। इस अभियान में 16 अवैध वैंडरों को पकड़कर हेतु रेलवे सुरक्षा बल के सुपुर्द किया गया। इसी क्रम में प्रयागराज छिवकी पर चलाये गए मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान में वाणिज्य विभाग के 15 टिकट चेकिंग स्टाफ ने रेलवे सुरक्षा बल व

राजकीय रेलवे पुलिस के 12 कर्मचारियों के सहयोग से अभियान चलाया। इस अभियान में 20 गाड़ियों को चेक कर 343 यात्रियों से 2,07,950/- रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। इसमें 117 यात्रियों से बिना टिकट यात्रा के लिए 1,05,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया, 221 यात्रियों से अनियमित टिकट पर यात्रा के लिए 1,01,250/- रुपये जुर्माना वसूला गया एवं 5 यात्रियों से गंदगी फैलाने के लिए के लिए 1000/- रुपये जुर्माना वसूला गया। इस अभियान में 2 अवैध वैंडरों को पकड़कर हेतु रेलवे सुरक्षा बल के सुपुर्द कर दिया गया। भारतीय रेल अधिनियम के अंतर्गत बिना टिकट या अनियमित टिकट पर यात्रा करना दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना, कारावास या दोनों का प्रावधान है। प्रयागराज मण्डल, उत्तर मध्य रेलवे अपने सभी सम्मानित यात्रियों से अपील करता है कि वे उचित और वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें और रेलवे को सुरक्षित एवं अनुशासित बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

एमएसडीई ने जन सेवा कार्यक्रम के चरण 2 के तहत

राष्ट्रीय कर्मयोगी सेवा-भाव प्रशिक्षण का आयोजन किया

सूत्र/रे.स.ब्यू. नागरिक-केंद्रित शासन और क्षमता निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, कोशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 9 जुलाई, 2025 को कोशल भवन, नई दिल्ली में "राष्ट्रीय कर्मयोगी सेवा-भाव" प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया। यह कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी ढांचे के अंतर्गत क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) की एक प्रमुख पहल का हिस्सा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीजीटी, आरडी-एसडीई, एनएसटीआई, एनआईएमआई, सीएसटीएआरआई और एनसीवीईटी सहित एमएसडीई क्षेत्रीय संस्थानों से नामित 28 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ये अधिकारी एमएसडीई के निदेशक श्री प्रीतम दत्ता और सीएसटीए-आरआई के निदेशक श्री टी. रागुलान थे। इन दोनों अधिकारियों को मई 2025 में सीबीसी द्वारा प्रमुख प्रशिक्षक के रूप में चुना गया था। तीन दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण सत्र के दौरान, अधिकारियों को सेवा-भाव को बढ़ावा देने, उद्देश्य-संचालित सार्वजनिक सेवा को मजबूत करने और अंतर संस्थागत सहयोग को गहरा करने के लिए विभिन्न उपकरणों और विधियों को सिखाया गया। प्रशिक्षण में चार संरचित

मॉड्यूल शामिल थे, जिनका उद्देश्य मानसिकता में बदलाव लाना, विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और अधिकारियों के बीच जवाबदेही की भावना को मजबूत करना था। केस अध्ययन, सहकर्मी शिक्षण और चिंतनशील चर्चाओं के माध्यम से, प्रतिभागियों ने पता लगाया कि वे सार्वजनिक सेवा वितरण में अधिक प्रभावी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। ये 28 अधिकारी अब अपने-अपने क्षेत्रीय संस्थानों में एक दिवसीय सेवा-भाव कार्यशालाओं का आयोजन करके परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, ताकि एमएसडीई प्रणाली में सभी स्तरों पर नागरिक प्रथम सेवा का संदेश पहुंचाया जा सके। सत्र पर विचार व्यक्त करते हुए, एमएसडीई के सचिव, श्री रजित पुन्हानी ने कहा, "राष्ट्रीय कर्मयोगी सेवा-भाव प्रशिक्षण एक अधिक उत्तरदायी, संवेदनशील और नागरिक-प्रधान प्रशासन के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उद्देश्य-संचालित शासन को पोषित करने के लिए तकनीकी क्षमता से आगे जाता है। अधिकारियों में सेवा की भावना का संचार करके, हम न केवल सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार कर रहे हैं, बल्कि विकसित भारत/2047 के हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप एक प्रतिभाशाली और सिद्धांतबद्ध कार्यबल भी विकसित करते हैं।" समापन सत्र

के दौरान, महानिदेशक (प्रशिक्षण) सुश्री त्रिशालजीत सेठी और कोशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के संयुक्त सचिव सुश्री हेना उस्मान ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने इस प्रशिक्षण के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला, जो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और मिशन-उन्मुख कार्यबल के निर्माण में मदद करता है। उन्होंने प्रतिभागियों से बातचीत भी की, उनके विचारों की सराहना की और जमीनी स्तर पर सेवा भाव की भावना को लागू करने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। यह प्रशिक्षण, जो मिशन कर्म योगी ढांचे का हिस्सा है, केन्द्र सरकार के अधिकारियों में सेवा-भाव की भावना पैदा करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि वे नियमित आधिकारिक कर्तव्यों से परे उद्देश्यपूर्ण सार्वजनिक सेवा की अवधारणा को अपना सकें। इस चरण के सफल समापन के साथ, एमएसडीई मानव संसाधन विकास में निरंतर निवेश के माध्यम से शासन की संस्कृति में बदलाव का नेतृत्व कर रहा है - जिससे एक सशक्त, सेवा-उन्मुख और नागरिक-केंद्रित अधिकारी-वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

Scan the Code for the Latest Verified
RAILWAYS NEWS ON OUR WEBSITE OR E-PAPER



SCAN QR

हमारी वेबसाइट या ई-पेपर पर भारतीय रेलवे के सत्यापित समाचार को पढ़ने के लिए कोड को स्कैन करें

www.railsamacharbureauald.com

वंदे भारत ने जीता जापानियों का दिल, ओसाका एक्सपो में भारतीय रेल की धूम



सूत्र/रे.स.ब्यू- जापान के ओसाका में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो-2025 में भारतीय रेल की धूम मची है। भारतीय पवेलियन में न केवल भारतीय प्रवासी बल्कि जापानी नागरिकों की भी भारी भीड़ उमड़ रही है। एक्सपो पहुंचने वाले लोगों में वंदे भारत एक्सप्रेस और चिनाब ब्रिज को लेकर जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। लोग इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। कई जापानी आगंतुकों को यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि भारत में इतनी तेज रफ्तार और अत्याधुनिक

सुविधाओं वाली ट्रेनें अब आम हो गई हैं। वंदे भारत की एयरोडायनमिक डिजाइन, इनबिल्ट सुरक्षा फीचर्स और सेमी हाई-स्पीड क्षमताओं ने तकनीक प्रेमियों को आकर्षित किया है। वहीं, चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। भारतीय रेल इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बनकर उभरा है। हिमालय की घाटियों में बना यह ब्रिज न केवल तकनीकी चुनौती को परास्त करता है, बल्कि भारत के उत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद अहम है।

जापानी दर्शक, खासकर इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के छात्र, चिनाब ब्रिज के 3D प्रेजेंटेशन और इंटरैक्टिव मॉडल को ध्यान से देख रहे हैं और इसके निर्माण से जुड़े विवरणों को जानने में गहरी रुचि ले रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन और चिनाब ब्रिज आधुनिक भारतीय रेल का चमकता सितारा है। बदलते भारत की पहचान है। बीते एक दशक में वंदे भारत ने अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ रेल यात्रा को नई पहचान दी है। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तेज रफ्तार यात्रा की सुविधा मिल रही है। भारतीय रेल ने देश के हर कोने में वंदे भारत के संचालन से

कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिखा है। पूरे देश में करीब 140 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसे वरिष्ठ नागरिकों के साथ युवाओं के बीच अपार लोकप्रियता मिली है। इस ट्रेन में वातानुकूलित कोच, स्वचालित दरवाजे, बायो टॉयलेट्स, जीपीएस सूचना प्रणाली, ऑनबोर्ड कैंटीन, वाई-फाई, और सीसीटीवी सुरक्षा जैसी सुविधाएं हैं। ये



सुविधाएं यात्रियों को एक प्रीमियम और आरामदायक अनुभव प्रदान करती हैं, जो पहले साधारण ट्रेनों में संभव नहीं था। वंदे भारत ट्रेनें वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।

विश्व एक्सपो 2025, जो कि 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपनी उपलब्धियों और नवाचारों को साझा करने का एक सुनहरा अवसर है। जापान में इंडिया पवेलियन की लोकप्रियता न केवल भारत की बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि दुनिया भारत की प्रगति को उत्सुकता और सम्मान की नजरों से देख रही है।



केंद्रीय चिकित्सालय में चिकित्सा सेवा में आध्यात्मिक विचारों की भूमिका पर सेमिनार का आयोजन



सूत्र/रे.स.ब्यू- रेल कर्मियों को बेहतर चिकित्सा सेवा देने के उद्देश्य से दिनांक 8 जुलाई 2025 को चिकित्सा निदेशक डॉ. एस. के. हण्डू की अध्यक्षता में चिकित्सा सेवा में आध्यात्मिक विचारों की भूमिका पर केंद्रीय चिकित्सालय उत्तर मध्य रेलवे में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ ने उत्साह से भाग लिया। मुख्य अतिथि श्री शेषनाथ पुष्कर भूतपूर्व राजभाषा अधिकारी, प्रयागराज मंडल ने अपनी संबोधन में कहा कि यह संसार विचारों से ही चलता है विचारों से ही संचालित होता है, विचार व्यक्ति को जिस दिशा में ले जाते हैं वह उसी दिशा में जाता है। आध्यात्मिक विचार, विचारों में श्रेष्ठ होते हैं और व्यक्ति को सही दिशा में ले जाते हैं। यह विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में अच्छी भावनाओं जैसे समानता की भावना, प्रेम की भावना सेवा और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। यह विचार बुरी भावनाओं जैसे असमानता की भावना, नफरत की भावना, असहयोग की भावना, बदले और दुश्मनी की भावना को रोकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में जितने भी महापुरुष और संत हुए हैं सभी ने समाज को आध्यात्मिक विचार ही दिए हैं। यदि हम उनके विचारों पर चलें तो हम अच्छा इंसान बन सकते हैं और हर क्षेत्र में चाहे वह चिकित्सा हो या इंजीनियरिंग हो या परिचालन हो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा इंसान हर एक काम अच्छा करता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक विचार मानता है कि इंसान से बड़ा कोई नहीं और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और जो डॉक्टर इस विचार पर चलेगा वह बेहतर काम करेगा। डॉ. एस. के. हण्डू ने अपने संबोधन में कहा कि आध्यात्मिक विचार व्यक्ति को सही और गलत की पहचान करने में सहयोग करते हैं। अच्छा विचार और अच्छी भावना की मदद से एक डॉक्टर सहानुभूति से मरीज का इलाज करता है। आध्यात्मिक विचारों में युक्त डॉक्टर खुशी और प्रेम से मरीजों की सेवा करता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग इस सेमिनार से लाभलेंगे और पहले से बेहतर सेवा मरीज को देंगे।

बड़रबी-सायरंग रेल लाइन से मिजोरम में बहेगी विकास की बयार

सूत्र/रे.स.ब्यू- वर्ष 2025 मिजोरम के इतिहास में एक मील का पत्थर बनकर दर्ज हुआ है। पहली बार इस पर्वतीय राज्य की राजधानी आइजोल को देश के ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि बड़रबी सायरंग ब्रॉड गेज रेल परियोजना के पूरा होने से संभव हो सकी है। यह न केवल मिजोरम, बल्कि समग्र पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम है। मिजोरम भारत का एक दूरस्थ, पहाड़ी और सीमावर्ती राज्य है, जिसकी सीमाएं उत्तर में असम और मणिपुर, पश्चिम में त्रिपुरा और बांग्लादेश तथा पूर्व व दक्षिण में म्यांमार से मिलती हैं। समुद्र से कटा होने और ऊबड़-खाबड़ भौगोलिक संरचना के कारण यह राज्य अब तक सड़क मार्ग पर ही निर्भर था। सीमित सड़क कनेक्टिविटी और अविकसित बुनियादी ढांचे के कारण यह क्षेत्र देश की मुख्यधारा से कटा-कटा महसूस करता था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 नवंबर 2014 को बड़रबी सायरंग रेल परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके बाद भूमि अधिग्रहण कार्य 2014-15 में पूर्ण किया गया और 2015-16 से निर्माण कार्य आरंभ हुआ। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यह परियोजना 2025 में पूरी हुई और जून 2025 में रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) ने इसके संचालन की अनुमति प्रदान की। परियोजना के अंतर्गत 51.38 किमी लंबी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया गया है, जिस पर 100 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रेनों का परिचालन संभव है। इस रेल खंड पर बड़रबी से सायरंग के बीच हॉर्तोंकी, कवनपुरी और मुआलखांग स्टेशन स्थित हैं। परियोजना में कुल 48 सुरंगें बनाई गई हैं, जिनकी कुल लंबाई 12.85 किमी



है। इसके अलावा, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल, 5 रोड ओवरब्रिज तथा 9रोड अंडरब्रिज भी बनाए गए हैं। इनमें से सबसे ऊंचा पुल 104 मीटर ऊंचा है, जो दिल्ली की कुतुबमीनार से भी ऊंचा है। इस परियोजना की कुल लागत ₹7,714 करोड़ आंकी गई है और इसके निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे (NFR) को दी गई थी। यह परियोजना मिजोरम के आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सड़क मार्ग की सीमाओं से जूझते इन लोगों को अब तेज, सुरक्षित और सस्ता परिवहन विकल्प मिलेगा। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी, बल्कि राज्य के युवाओं को रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी मिलेंगे। कृषि क्षेत्र में भी इसका प्रभाव दूरगामी होगा। स्थानीय किसान अब अपने कृषि उत्पादों को देश के विभिन्न बाजारों तक कम लागत और कम समय में पहुंचा सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा। इससे राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से भी यह रेलवे

लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिजोरम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सुरंगें, घाटियाँ और पुल इस रेल यात्रा को यादगार अनुभव में बदल देंगे। इससे न केवल घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका सामरिक महत्व है। म्यांमार सीमा के करीब होने के कारण यह रेलवे लाइन भारत की सामरिक रणनीति को भी मजबूती देती है। यह भविष्य में दक्षिण-पूर्व एशिया तक रेलवे संपर्क के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है और भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को गति देने वाला एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब मिजोरम की राजधानी आइजोल भी भारतीय रेल मानचित्र पर दर्ज हो चुकी है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर की अन्य राज्य राजधानियाँ गुवाहाटी (असम), इटानगर (अरुणाचल प्रदेश), अगरतला (त्रिपुरा), और शिलांग (मेघालय) (हालांकि शिलांग आंशिक रूप से) ब्रॉड गेज नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। इस परियोजना के दौरान मौसम, भूगोल और संसाधनों की जो चुनौतियाँ सामने आईं, उन्होंने भारतीय रेल की इंजीनियरिंग क्षमता, प्रबंधन दक्षता और दूर दृष्टि को प्रमाणित किया। क्षेत्र में वर्षभर केवल 4-5 महीने ही निर्माण कार्य संभव था, शेष समय वर्षा और भूस्खलन के कारण कार्य अवरुद्ध रहता था। संकरी और तीव्र ढाल वाली सड़कों पर निर्माण सामग्री को बड़े ट्रकों से उतार कर छोटे वाहनों से ढोया गया। साथ ही, श्रमिकों की कमी, नेटवर्क की समस्याएं और भौगोलिक अलगाव जैसी बाधाओं के बावजूद परियोजना समयबद्ध रूप से पूरी की गई। बड़रबी सायरंग रेलवे परियोजना मिजोरम के विकास की नई रेल बन चुकी है जो कनेक्टिविटी से कहीं आगे, एक सामाजिक, आर्थिक और सामरिक बदलाव का वाहक बन चुकी है।



पेटल्स प्ले स्कूल" की उद्घाटन किया गया। रेलगाँव कॉलोनी वह स्थान है जहा उत्तर मध्य रेलवे के अनेक अधिकारी व कर्मचारी परिवार सहित निवास करते हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से एक ऐसे प्ले स्कूल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो छोटे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ-साथ एक रचनात्मक, सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान कर सके। इसी आवश्यकता को संगठन की अध्यक्ष श्रीमती

चेतना जोशी ने गंभीरता से संज्ञान में लिया और 2 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से इस विचार को साकार रूप दिया। वातानुकूलित कक्ष, सीसीटीवी निगरानी, ऑडियो-विजुअल शिक्षण, सुरक्षित खेल क्षेत्र व न्यूनतम शुल्क जैसी सुविधाओं से युक्त यह विद्यालय बच्चों को एक समग्र, आधुनिक और सुरक्षित शिक्षा परिवेश प्रदान करेगा। इस अभिनव पहल में संगठन की

सचिव श्रीमती ऋचा वर्मा, सदस्या श्रीमती एस. उमा सहित संगठन की अन्य सदस्याओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने अपनी सक्रिय सहभागिता से इस प्रयास को साकार रूप देने में सहयोग किया। यह पहल नन्हे सपनों को सहेजने की दिशा में उत्तर मध्य रेलवे का एक प्रेरणादायक कदम है।

बाल विकास की दिशा में उत्तर मध्य रेलवे की अभिनव पहल - उत्तर मध्य रेलवे द्वारा रेलगाँव कॉलोनी, सूबेदारगंज में प्ले स्कूल 'प्रयाग पेटल्स' का शुभारंभ



हर विकसित समाज की बुनियाद एक मजबूत बचपन से होती है, और जब बचपन को सही दिशा, संरक्षण और शिक्षा मिले, तो वह समाज के उज्ज्वल कल की आधारशिला बनता है। इसी विश्वास को आधार बनाते हुए उत्तर मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन, मुख्यालय द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2025 को रेलगाँव कॉलोनी, सूबेदारगंज में "प्रयाग

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में मंडल रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

सूत्र/रे.स.ब्यू- पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल की मंडल रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति (DRUCC) की बैठक हाल ही में मुंबई सेंट्रल स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह ने की और कार्यवाही का संचालन मुंबई सेंट्रल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अभय सिंह चौहान ने किया। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, उपभोक्ता अधिकार, दिव्यांगजन, यात्री संघों जैसे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले डीआरयूसीसी सदस्यों और माननीय संसद सदस्यों द्वारा नामित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। बैठक में श्री अरविंद रामलखन यादव, श्री रामगोपाल शर्मा, श्री नीलेश श्याम शाह, एडवोकेट मिलिंद बालू कापड़े, श्री महेंद्र शिवराज कोठारी, श्री राजीव सिंघल, श्री संजयकुमार सी. शाह, श्री आशीष एच. शाह, श्री जगदीश जयसिंह सोलंकी, श्री रमणिक लालजी सांगोई, श्री हसमुख भवंजी गाला, श्री देविस ई. टी. और श्रीमती जयश्री उमेश बल्लिकर उपस्थित थे। उनकी सक्रिय भागीदारी और

रचनात्मक प्रतिक्रिया ने विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बैठक के दौरान सदस्यों ने यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। चर्चा मुख्य रूप से उपनगरीय स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैंप, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी बेहतर सुविधाएँ शुरू करने और प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित रही। उपनगरीय स्टेशनों पर एस्केलेटर की व्यवस्था से संबंधित एक उल्लेखनीय सुझाव को उसके संरचित, व्यावहारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए मंडल प्रशासन से विशेष सराहना मिली। इसके अलावा, रेलवे परिसर में लावारिस पाए गए बुजुर्गों की सहायता के लिए कार्यरत एक सामाजिक संगठन के बारे में जानकारी साझा की गई, जो एक दयालु और सामाजिक रूप से जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। समिति के सदस्यों और रेलवे अधिकारियों के बीच सार्थक बातचीत के साथ बैठक सकारात्मक और रचनात्मक रूप से संपन्न हुई। मंडल रेल प्रशासन ने सुविधाओं के उन्नयन और उपयुक्त सुझावों का प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

कोचिंग सेंटर अब 'पोचिंग सेंटर' बन गए हैं, ये प्रतिभाओं के लिए ब्लैक होल बन गए हैं : उपराष्ट्रपति

उत्तम ग्रेड और मानकीकृत अंकों की दौड़ ने जिज्ञासा को दबा दिया है : उपराष्ट्रपति

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा, "कोचिंग सेंटर अब 'पोचिंग सेंटर' बन गए हैं। वे प्रतिभाओं के लिए ब्लैक होल बन गए हैं। कोचिंग सेंटर तेजी से फैल रहे हैं। यह हमारे युवाओं के लिए खतरनाक है, जो हमारे भविष्य हैं। हमें इस चिंता जनक बुराई से निपटना ही होगा। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को इस तरह कलंकित और दूषित नहीं होने दे सकते। श्री धनखड़ ने आगे कहा, "अब राष्ट्रों को सेनाओं द्वारा नहीं, बल्कि एल्गोरिद्म के जरिए नियंत्रण में लाया जाएगा, क्योंकि सेनाओं की जगह अब एल्गोरिद्म ने ले ली है। संप्रभुता अब आक्रमणों से नहीं, बल्कि विदेशी डिजिटल ढांचे पर निर्भरता के कारण खोएगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल युग में वैश्विक शक्ति की गतिशीलता कैसे बदल रही है, और कहा, "21वीं सदी का युद्धक्षेत्र अब जमीन या समुद्र नहीं है। पारंपरिक युद्ध के दिन अब बीत चुके हैं। हमारी क्षमता, हमारी शक्ति का निर्धारण कोड, क्लाउड और साइबर द्वारा किया जाना चाहिए।" राजस्थान के कोटा स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) के चौथे दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा, "आज हम गुरुकुल की बात कैसे कर सकते हैं - भारतीय संविधान में 22 दृश्य चित्रणों में एक गुरुकुल की भी छवि है। हम

हमेशा से ज्ञान के दान में विश्वास करते रहे हैं। कोचिंग सेंटरों को अपने बुनियादी ढांचे का उपयोग कौशल केंद्रों में बदलने के लिए करना चाहिए। मैं सिविल सोसाइटी और मेरे सामने और बाहर मौजूद जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ कि वे इस बीमारी की गंभीरता को समझें। उन्हें शिक्षा में विवेकशीलता बहाल करने के लिए एकजुट होना होगा। हमें कौशल के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है," उन्होंने कहा। श्री धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि अंकों के प्रति जुनून सीखने की भावना को किस प्रकार नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा, "उत्तम ग्रेड और मानकीकृत अंकों के प्रति जुनून ने जिज्ञासा को नुकसान पहुंचाया है, जो मानव बुद्धि का एक अभिन्न पहलू है। सीटें सीमित हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर पूरे देश में फैले हुए हैं। वे सालों तक छात्रों के दिमाग को तैयार करते हैं और फिर उन्हें रोज़ोद बना देते हैं। उनकी सोच पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है। इससे कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं।" श्री धनखड़ ने शिक्षा को असेंबली लाइन की तरह मानने के विचार का कड़ा विरोध करते हुए कहा, "हमें इस असेंबली लाइन संस्कृति को समाप्त करना होगा, क्योंकि यह संस्कृति हमारी शिक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। कोचिंग सेंटर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रवाह के विरुद्ध हैं। यह विकास और प्रगति में अनावश्यक रुकावटें और बाधाएं पैदा करता है।

पाठकों से अनुरोध

आपको यह अंक कैसा लगा? इसमें आप और क्या परिवर्तन चाहते हैं? कृपया अपने सुझावों से अवश्य ही अवगत कराएं जिससे हम पत्रिका में सुधार कर सकें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा।

प्रधान संपादक

पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षों की भौति आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

सहयोग राशि:

- उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
- उच्च अधिकारी- 3500 रु. मात्र
- अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
- रेलकर्मी/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

पंजीकृत कार्यालय

502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड,
नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003
से प्रकाशित।

कॉप कार्यालय- अनिल केन (रिपोर्टर)
कार्यालय 8439 आर्य नगर
पहाड़गंज दिल्ली-55

समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव वि.
इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि.
329/255 चक. जीरो रोड
इलाहाबाद से मुद्रित एवं 502
पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर,
कीडगंज प्रयागराज-211003
से प्रकाशित।
आर.एन. आई नं. 51097-90
पोस्ट ए.डी.-8
मो. 9773946044 / 9793956044
फोन नं. 0532-2418040

लेख



रेल का बदलता हुआ परिदृश्य-आज के परिप्रेक्ष्य में

भारतीय रेल की कहानी मात्र एक यातायात सेवा की नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक चेतना की गाथा है। यह न केवल गाँवों और शहरों को जोड़ती है, बल्कि दिलों को भी जोड़ती है। 1853 में जब पहली रेलगाड़ी बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यह सेवा विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली बन जाएगी। समय के साथ-साथ भारतीय रेल का स्वरूप बदलता रहा है, और आज यह बदलाव तीव्र गति से तकनीकी, पर्यावरणीय, प्रशासनिक एवं यात्री-केन्द्रित रूप में स्पष्ट देखा जा सकता है। 21वीं सदी की रेल भारतीय तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रही है। जहां एक ओर टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन लोकेशन की जानकारी अब मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर ट्रेनों में सेंसर आधारित मॉनिटरिंग, GPS ट्रैकिंग और फुली एयर-कंडीशंड मॉडर्न कोचों का प्रयोग हो रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, भारत की पहली सेमी-हाई स्पीड ट्रेन, न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि रेलवे के बदलते दर्शन को भी दर्शाती है। इसकी डिजाइन, संचालन प्रणाली, और तेज गति यह स्पष्ट करती है कि भारतीय रेल अब "मात्र चलने वाली गाड़ी" नहीं, बल्कि स्मार्ट और सशक्त राष्ट्र निर्माण की धुरी बन चुकी है। रेलवे सुरक्षा का विषय सदैव संवेदनशील रहा है। इस दिशा में 'कवच' (Train Collision Avoidance System) एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यह भारत में विकसित किया गया एक स्वदेशी सुरक्षा तंत्र है, जो ट्रेन टक्कर जैसी घटनाओं को रोक सकता है। इसके अलावा, कई ट्रेनों में CCTV कैमरे, फायर अलार्म सिस्टम, स्वचालित दरवाजे, और बायो-टॉयलेट्स जैसी सुविधाएँ शामिल की जा रही हैं। स्टेशनों पर फेस रिकग्निशन आधारित सुरक्षा प्रणाली और रेलवे पुलिस की उपस्थिति को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। आज के युग में विकास का अर्थ केवल तकनीकी विस्तार नहीं, बल्कि पर्यावरण के

प्रति उत्तरदायित्व भी है। भारतीय रेल दुनिया की पहली "नेट जीरो कार्बन एमिशन रेलवे" बनने की दिशा में कार्य कर रही है। रेलवे ने कई स्टेशनों पर सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वैस्टिंग सिस्टम, और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाए हैं। 'एक स्टेशन एक सौर ऊर्जा संयंत्र' और 'हरित स्टेशन' जैसी योजनाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हाइड्रोजन-चालित ट्रेनों का प्रयोग और विद्युतीकरण के तेजी से हो रहे कार्य यह दर्शाते हैं कि रेलवे न केवल रफ्तार पर ध्यान दे रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी अपनी प्राथमिकता बना चुकी है। भारतीय रेल अब यात्री को केवल 'यात्री' नहीं मानती, बल्कि उसे 'ग्राहक' और 'सहभागी' मानकर योजनाएं बना रही है। स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट, स्मार्ट टिकटिंग कियोस्क, क्लीन टॉयलेट्स, और वाई-फाई जैसी सेवाएँ इस दिशा में कदम हैं। रेलवे द्वारा संचालित 'उदयन', 'सप्तक्रांति', 'अवध एक्सप्रेस' जैसी ट्रेनों में क्षेत्रीय पहचान, खानपान और आतिथ्य को प्रमुखता दी जा रही है। वहीं 'वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट' योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में रेल यात्रा की दिशा ही बदलने वाली है। जापानी तकनीक से संचालित यह परियोजना केवल तेज गति की बात नहीं करती, बल्कि सटीकता, सुरक्षा और स्वच्छता के उच्चतम मानकों की बात करती है। इसके अलावा सेमी हाई-स्पीड कॉरिडोर, Dedicated Freight Corridors, और AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भविष्य की रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। रेलवे केवल लोहे की पटरियों और इंजनों का जाल नहीं है, बल्कि यह भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह परिवर्तन, प्रवास, पुनर्मिलन, विदाई, व्यापार, संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक है। रेल की खिड़की से झांकता

भारत कभी किसी किसान का खेत दिखाता है, कभी किसी गाँव की झोपड़ी, और कभी किसी नगर की चमक। इन दृश्यों में भारत की आत्मा बसती है, और रेल उसे हर कोने तक पहुँचाती है। रेलवे ने अब अपनी प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल बनाया है। ई-टेंडरिंग, HRMS पोर्टल, पेपरलेस ऑफिस, ई-ऑफिस, और रीयल टाइम डेटा एनालिटिक्स जैसे माध्यमों से रेलवे संचालन अब पहले से अधिक पारदर्शी, तेज और जवाबदेह हो चुका है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे के परिदृश्य में जो परिवर्तन हो रहा है, वह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सोच, दृष्टिकोण और कार्यशैली में व्यापक बदलाव का संकेत देता है। रेल अब केवल एक गाड़ी नहीं, बल्कि देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक शक्ति बनती जा रही है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण, पर्यावरणीय चुनौतियाँ और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में रेलवे की भूमिका अब केवल 'सफर' कराने की नहीं, बल्कि 'विकास पथ' बनाने की हो चुकी है। यह परिवर्तनशील परिदृश्य आने वाले वर्षों में और भी प्रेरणादायक और सशक्त बनकर सामने आएगा।



सत्येन्द्र कुमार, अनुवाद अधिकारी,
इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
साकेत, नई दिल्ली

दूरसंचार विभाग ने युवाओं को डिजिटल एम्बेसेडर के रूप में सशक्त बनाने के लिए देश भर में संचार मित्र योजना शुरू की

संचार मित्र, यानी छात्र स्वयंसेवक, डिजिटल साक्षरता और दूरसंचार जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) के क्षेत्रीय कार्यालय, असम एलएसए ने गुवाहाटी स्थित बीएसएनएल भवन में आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी और असम के अन्य इंजीनियरिंग कलेजों सहित प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य हाल ही में शुरू की गई संचार मित्र योजना के बारे में जानकारी देना और उसका विस्तार करना था। इस अभिनव पहल का उद्देश्य नागरिकों और दूरसंचार इको-सिस्टम के बीच संचार प्रणाली की कमी को दूर करने के लिए छात्र स्वयंसेवकों को डिजिटल एम्बेसेडर के रूप में शामिल करना है। श्री हेमैंद्र कुमार शर्मा ने डिजिटल क्रांति में दूरसंचार सेवाओं की भूमिका और भारत के उपभोक्ता से विभिन्न अत्याधुनिक दूरसंचार सेवाओं और उत्पादों के प्रदाता बनने के परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर जन जागरूकता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में 'डिजिटल एम्बेसेडर' के रूप में संचार मित्रों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और इस योजना से जुड़ने के लिए अत्यधिक उत्साह दिखाया। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने संशोधित 'संचार मित्र योजना' का शुभारंभ किया और इसे एक पायलट पहल से एक सशक्त, व्यापक

और प्रोत्साहन-संचालित राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। यह योजना भारत की युवा शक्ति - छात्र स्वयंसेवकों - की शक्ति को दूरसंचार जागरूकता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण के जागरूक दूत बनाने के लिए तैयार की गई है। श्री सिंधिया ने इस योजना को एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया है जो चार 'डी' - लोकतंत्र, जनसांख्यिकी, डिजिटलीकरण और वितरण - में भारत के नेतृत्व का प्रतीक है। **संचार मित्र योजना:** शुरुआत में चुनिंदा संस्थानों में शुरू की गई संचार मित्र योजना को अब अपने पायलट चरण में उत्साहवर्धक रुचि और आशाजनक प्रभाव के बाद देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए विस्तारित किया गया है। इस योजना के तहत, संचार मित्र के रूप में नामित किए गए छात्र स्वयंसेवकों को डिजिटल सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम और ईएमएफ विकिरण संबंधी चिंताओं जैसे प्रमुख दूरसंचार मुद्दों के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही, मोबाइल के जिम्मेदार इस्तेमाल और डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। विस्तारित संचार मित्र योजना का उद्देश्य न केवल जन जागरूकता बढ़ाना है, बल्कि भाग लेने वाले छात्रों को 5जी, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा सहित अत्याधुनिक दूरसंचार तकनीकों से परिचित कराना भी है। निर्धारित प्रशिक्षण, परियोजना में भागीदारी और वास्तविक दुनिया की दूरसंचार पहलों से जुड़ाव के माध्यम से, इस

योजना का उद्देश्य डिजिटल रूप से जागरूक, कुशल और अनुसंधान-उन्मुख युवा कार्यबल का निर्माण करना है। स्थानीय दूरसंचार विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों के परामर्श से भागीदार संस्थानों की पहचान की जाएगी और प्रासंगिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि - दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, साइबर सुरक्षा - के छात्रों को संचार मित्र के रूप में नामित किया जाएगा। संचार मित्रों को क्षेत्र के विशेषज्ञों और राष्ट्रीय संचार अकादमी- प्रौद्योगिकी (एनसीए-टी) तथा दूरसंचार विभाग के मीडिया विंग के विशेषज्ञों से आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। संचार मित्र जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएंगे, समुदायों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ जुड़ेंगे और अपने परिवेश में जागरूक डिजिटल व्यवहार के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे। उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रतिभागियों का समय-समय पर नवाचार, निरंतरता और आउटरीच प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को इंटरनशिप, राष्ट्रीय दूरसंचार परियोजनाओं में भागीदारी, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जैसे उच्च-स्तरीय मंचों में भागीदारी और आईटीयू मानकों और नीतिगत कार्यों से जुड़ाव सहित विशेष अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। संचार मित्र योजना के माध्यम से युवाओं की यह रणनीतिक भागीदारी भारत के दूरसंचार अनुसंधान, विकास और विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सावन: शिव से जीवन का सत्य सीखने का समय

सूत्र/रे.स.ब्यू- श्रावण मास, जिसे हम सावन के नाम से जानते हैं, भारतीय संस्कृति में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह मास भगवान शिव को समर्पित होता है वह देव जिनकी सादगी, करुणा, त्याग और तितिक्षा की भावना हमें जीवन के गूढ़तम पाठ सिखाती है। सावन केवल व्रत, जलाभिषेक और भक्ति गीतों का समय नहीं है, यह एक अवसर है महादेव के गुणों को अपने जीवन में उतारने का। शिव, जिनका रहन-सहन अत्यंत साधारण है, हमें सिखाते हैं कि आडंबर से दूर रहकर भी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उनका गले में विष धारण करना, हमें यह सिखाता है कि समाज में विषैली परिस्थितियों को स्वयं में समाहित करके भी दूसरों के लिए अमृत समान व्यवहार किया जा सकता है। महादेव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, बल्कि विवेक और अंतर दृष्टि का भी संकेत है। आज जब हम सामाजिक, पारिवारिक



और व्यक्तिगत चुनौतियों से घिरे हैं, तब शिव से यह सीखना आवश्यक है कि निर्णय कैसे धैर्य और गहराई से लिए जाएं। उनका ध्यानमग्न स्वरूप हमें आत्म-संयम और मानसिक शांति का महत्व सिखाता है। सावन में लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं, उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। पर क्या हम उनके भीतर छिपे मूल संदेश को समझते हैं? त्याग, संतुलन, समर्पण और सेवा, यही है शिव का मार्ग। शिव से सीखें कि कैसे क्रोध में भी करुणा, तांडव में भी सृजन और संहार में भी समभाव होता है। आज के समय में, जब व्यक्ति बाहरी चमक- दमक और भौतिक सुखों की दौड़ में अपनी आत्मा की शांति खो बैठा है, शिव का मार्ग उसे भीतर की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। सावन का यह पावन मास एक आत्मनिरीक्षण का अवसर है एक ऐसा क्षण जब हम महादेव से पूछ सकते हैं: हम जीवन को कैसे सरल, सच्चा और शिवमयी बना सकते हैं?



कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ सहयात्रियों का सम्मान भी जरूरी

श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति में लीन कांवड़ यात्री देश के विभिन्न हिस्सों से हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य तीर्थ स्थलों की ओर निकलते हैं। इस पवित्र यात्रा में रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लाखों यात्री ट्रेनों के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इस दौरान रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भारी भीड़ का दबाव देखा जाता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि कांवड़ यात्री अपनी यात्रा को आस्था के साथ-साथ अनुशासन और सहिष्णुता के साथ करें। रेलवे स्टेशन सार्वजनिक स्थल हैं, जहाँ हर आयु वर्ग, हर परिस्थिति से जुड़े लोग यात्रा करते हैं। ट्रेनों में अक्सर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और बीमार यात्री भी होते हैं, जिनके लिए धक्का-मुक्की, तेज शोर, और बेतरतीब व्यवहार परेशानियों का कारण बनता है। कई बार देखा गया है कि कुछ कांवड़ यात्रियों द्वारा ट्रेनों में जोर-जबरदस्ती से सीटों पर कब्जा, तेज आवाज में डीजे बजाना या रेल परिसरों में अव्यवस्था फैलाना आम यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। यह न केवल असंवेदनशीलता का परिचायक है, बल्कि एक धार्मिक यात्रा की गरिमा के भी विरुद्ध है। धार्मिक आस्था का यह पर्व अनुशासन और समर्पण की मिसाल होनी चाहिए। यात्रियों को चाहिए कि वे रेलवे नियमों का पालन करें, ट्रेनों में निर्धारित सीटों पर ही बैठें, सफाई का ध्यान रखें और सहयात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखें। रेल प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों और अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है, इसमें सहयोग देना यात्रियों का भी कर्तव्य है। रेलवे स्टेशनों पर कतार में खड़ा रहना, चढ़ने-उतरने में धैर्य बनाए रखना, और प्लेटफॉर्म पर अनुशासन बनाए रखना, यही सच्चे भक्त की पहचान है। धर्म वही है जो दूसरों को कष्ट न दे। कांवड़ यात्रा को सहनशीलता, समर्पण और सद्भाव का प्रतीक बनाएं ताकि रेलवे में सफर हर किसी के लिए सुखद और सुरक्षित बना रहे।

यूआईडीएआई ने माता-पिता और अभिभावकों से बच्चों के आधार बायोमेट्रिक्स अपडेट करने का आग्रह किया, 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क

अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट से स्कूल प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लाभों तक निर्बाध पहुँच संभव

सूत्र/रे.स.ब्यू- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उन बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) पूरा करने पर बल दिया है, जो सात वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आधार में अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं किए हैं। यह आधार के अंतर्गत आवश्यक है और माता-पिता या अभिभावक किसी भी आधार सेवा केंद्र या निर्दिष्ट आधार केंद्र पर अपने बच्चे का विवरण अपडेट कर सकते हैं।

5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक्स निःशुल्क अपडेट करें

पाँच वर्ष से कम आयु का बच्चा फोटोग्राफ, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और प्रमाण के दस्तावेज प्रदान करके आधार के लिए नामांकन करा सकता है। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार नामांकन के लिए उनके फिंगरप्रिंट और आईरिस बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते क्योंकि उस आयु तक वे परिपक्व नहीं होते। इसलिए वर्तमान नियमों के अनुसार बच्चे के पाँच वर्ष की आयु पूरी होने पर उसके आधार में फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से अपडेट किए जाने चाहिए। इसे पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) कहा जाता है। यदि बच्चा पाँच से सात वर्ष की आयु के बीच एमबीयू

करवाता है, तो यह निःशुल्क है। लेकिन सात वर्ष की आयु के बाद, केवल 100 रुपये का निर्धारित शुल्क है। बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एमबीयू का समय पर पूरा होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। यदि 7 वर्ष की आयु के बाद भी एमबीयू पूरा नहीं किया जाता है, तो वर्तमान नियमों के अनुसार आधार संख्या निष्क्रिय की जा सकती है।

नामांकन से अवसर तक – आधार हर कदम पर सशक्त बनाता है

अपडेट किए गए बायोमेट्रिक्स वाला आधार जीवन को आसान बनाता है और स्कूल में प्रवेश, प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण, छात्रवृत्ति का लाभ उठाने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में आधार के निर्बाध उपयोग को सुनिश्चित करता है। माता-पिता/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों/आश्रितों के बायोमेट्रिक्स को आधार में प्राथमिकता के आधार पर अपडेट करें। यूआईडीएआई ने ऐसे बच्चों के आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एमबीयू प्रक्रिया पूरी करने के लिए एसएमएस संदेश भेजना शुरू कर दिया है।

विज्ञान के माध्यम से राज्यों का सशक्तिकरण: नीति आयोग ने राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा जारी की

सूत्र/रे.स.ब्यू-भारत में विकेंद्रीकृत नवाचार को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, नीति आयोग ने अपनी रणनीतिक रिपोर्ट जारी की। इसका शीर्षक ‘‘राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को सुदृढ़ बनाने की रूपरेखा’’ है। इस रिपोर्ट का आधिकारिक विमोचन नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के महानिदेशक एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के सचिव डॉ.एन. कलैसेल्वी भी उपस्थित थे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रनय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. शिवकुमार कल्याणरमनय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई) के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पहल के लिए व्यापक संस्थागत समर्थन पर बल दिया। रिपोर्ट जारी करने की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए, नीति आयोग के वरिष्ठ

सलाहकार, प्रो. विवेक कुमार सिंह ने रिपोर्ट की उत्पत्ति और रणनीतिक उद्देश्य का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने राष्ट्रीय नीति को स्थानीय विकास आवश्यकताओं के साथ जोड़ने में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने विस्तार से बताया कि क्षेत्रीय परामर्श, राष्ट्रीय कार्यशाला और व्यापक बहु-हितधारक सहभागिता की समावेशी प्रक्रिया के माध्यम से इस रूपरेखा को कैसे आकार दिया गया। डॉ. वी.के. सारस्वत ने राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की उभरती भूमिका पर विचार किया। उन्होंने उन्नत तकनीकी-प्रशासनिक नेतृत्व, मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) डेटा प्रणालियों की आवश्यकता एवं अनुसंधान संस्थानों, उद्योगों और जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों को साझा मंच पर लाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा, ‘‘21वीं सदी की माँगों को पूरा करने के लिए, हमारी राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को न केवल प्रशासनिक इकाइयों के रूप में, बल्कि एकीकृत नवाचार पारिस्थिति की तंत्र के रूप में भी काम करना चाहिए।’’ मुख्य भाषण में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों को मिशन-उन्मुख संस्थानों में बदलने के रणनीतिक महत्व पर बल दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयासों को स्थानीय विकास प्राथमिकताओं के साथ जोड़ने का

आग्रह किया। उन्होंने सह-वित्तपोषण तंत्रों के माध्यम से नवाचार वित्तपोषण को समर्थन देने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, ‘‘राज्यों को केवल सरकारी आवंटन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए - उद्योगों को भी नवाचार मूल्य श्रृंखला में भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए।’’ डॉ. सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा या कृषि-नवाचार जैसी साझा क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर राज्यों के रणनीतिक संयोजन की भी वकालत की। मंत्री ने यह भी कहा, ‘‘ऐसे विषयगत समूह राज्यों को एक-दूसरे से सीखने, संसाधनों को एकत्रित करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सामूहिक शक्ति का निर्माण करने का अवसर प्रदान कर सकते हैं।’’ इस अवसर पर, श्री सुमन बेरी ने संघीय शासन के व्यापक ढाँचे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदें, सही उपकरणों, नेतृत्व और स्वायत्तता से सशक्त होकर, नवाचार के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती हैं। यह रूपरेखा स्थानीय रूप से प्रासंगिक, राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित वैज्ञानिक प्रगति के लिए आवश्यक संस्थागत आधार तैयार करने का प्रयास है।’’

10 लाख नागरिकों को मिलेगा निशुल्क एआई प्रशिक्षण: ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को दी जाएगी प्राथमिकता

एआई प्रशिक्षण, आईआरसीटीसी सेवाएं और राज्य एकीकरण सीएससी नेटवर्क को मजबूत करेंगे: केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

सूत्र/रे.स.ब्यू- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, द्वारका, नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। इस भव्य समारोह ने देश भर में परिवर्तनकारी डिजिटल सशक्तिकरण के एक दशक को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति रही। श्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में, श्री वैष्णव ने कहा, ‘‘देश भर के वीएलई भाई-बहनों ने डिजिटल इंडिया का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाकर एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब दुनिया यह सवाल उठा रही थी कि एक चायवाला या सब्जीवाला डिजिटल भुगतान कैसे कर सकता है, तो आज वह सपना साकार हो गया है। यूपीआई भुगतान वीजा लेनदेन से अधिक हो रहे हैं। यह 1.4 अरब भारतीयों की ताकत है।’’ उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सीएससी देश के लगभग 90 प्रतिशत गांवों तक पहुंच चुका है और कहा, ‘‘यदि हर गांव तक पहुंचने में सक्षम कोई माध्यम है, तो वह सीएससी है।’’ श्री वैष्णव ने मयूरभंज जिले की वीएलई मंजुलता और मेघालय की वीएलई रोज एंजेलिना की प्रेरक कहानियों का उदाहरण दिया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, दोनों महिलाओं ने डिजिटल कौशल प्राप्त किए और अपने समुदायों को सशक्त बनाया। उन्होंने आगे कहा, ‘‘मेघालय के ईस्ट वेस्ट खासी हिल्स की मनोरम पहाड़ियों और सुदूर गांवों के बीच, महिला वीएलई रोज एंजेलिना एम. खारसिंट्यू ने एक डिजिटल क्रांति की पटकथा लिखी है। मैरांग क्षेत्र में अपने केंद्र के माध्यम से, वह न केवल सेवाएँ प्रदान कर रही हैं, बल्कि परिवर्तन, सशक्तिकरण और सामुदायिक सेवा की एक मिसाल भी कायम कर रही हैं।’’

श्री वैष्णव ने निम्नलिखित प्रमुख घोषणाएं भी कीं:

- 10 लाख व्यक्तियों के लिए निशुल्क एआई प्रशिक्षण, सभी वीएलई को प्राथमिकता।
- सभी वीएलई से आईआरसीटीसी सेवाएं शुरू करने का आग्रह।
- राज्य आईटी एजेंसियों को सीएससी-एसपीवी के साथ एकीकृत

करने के लिए मुख्यमंत्रियों से बात करने के लिए प्रतिबद्ध। वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने डिजिटल अंतराल को समाप्त करने में सीएससी की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘डिजिटल इंडिया के लाभों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प हमारे वीएलई भाइयों और बहनों की मदद से आगे बढ़ाया जा रहा है। दस साल पहले, जब हमने डिजिटल इंडिया पहल शुरू की थी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक विकसित भारत की नींव रखने का दृष्टिकोण रखा था।’’ उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में जहां केवल 83,000 सीएससी केंद्र थे, जबकि आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 5.50 लाख हो गई है। उन्होंने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसएस) को सीएससी के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया और 74,000 से ज्यादा महिला वीएलई का जिक्र किया जो सशक्तिकरण के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं और यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। समय के साथ, हमें लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।’’ उन्होंने जागरूकता, साइबर सुरक्षा और विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में क्षमता निर्माण को मजबूत करने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने वीएलई को अपनी आय बढ़ाने के लिए अपडेटेड क्लाइंट लाइट और राज्य सरकार की सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देने की सिफारिश की। गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए, सीएससी एसपीवी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री संजय राकेश ने कहा, ‘‘सीएससी के साथ सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शहरों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीएससी केंद्र देश के दूरदराज के इलाकों में घर-घर जाकर जी2सी और बी2बी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे डिजिटल सशक्तिकरण को बल मिल रहा है।’’ उन्होंने यह भी कहा, ‘‘पिछले 10 वर्षों में सीएससी डिजिटल इंडिया के एक ऐसे मॉडल के रूप में उभरा है जो समावेशिता और सशक्तिकरण के एक नए प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए, हम देश को नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे।’’

पारंपरिक चिकित्सा में एआई पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के महत्वपूर्ण संक्षिप्त विवरण में भारत के आयुष नवाचारों को शामिल किया गया।

भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश: डब्ल्यूएचओ आयुष क्षेत्र का आर्थिक विकास में योगदान डब्ल्यूएचओ ने भारत के 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पर ध्यान दिया

सूत्र/रे.स.ब्यू. वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने “पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मापन” शीर्षक से एक तकनीकी संक्षिप्त विवरण जारी किया है। इसमें पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, विशेष रूप से आयुष प्रणालियों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एकीकृत करने में भारत के अग्रणी प्रयासों की सराहना की गई है। यह विवरण इस विषय पर भारत के प्रस्ताव के बाद जारी किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक चिकित्सा में एआई के अनुप्रयोग हेतु डब्ल्यूएचओ का पहला रोडमैप विकसित हुआ है। अपनी आयुष प्रणालियों की क्षमताओं को उन्नत और व्यापक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की क्षमता का लाभ उठाने के भारत के प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो देश को डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण में एक वैश्विक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी (जीपीएआई) शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा, “हमने ‘सभी के लिए एआई’ की भावना से प्रेरित होकर सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम

विकसित किए हैं। हमारा प्रयास सामाजिक विकास और समावेशी विकास के लिए एआई की क्षमताओं का पूरा लाभ उठाना है।” केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी विवरण में उल्लिखित भारत की एआई-आधारित पहल, अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, “यह मान्यता पारंपरिक चिकित्सा की वैश्विक प्रासंगिकता का विस्तार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती तकनीकों का उपयोग करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। एआई को आयुष प्रणालियों के साथ एकीकृत करके और आयुर्वेदिक के ऐतिहासिक छाप प्रदर्शन (एसएएचआई) पोर्टल, राष्ट्रीय आयुष रुग्णता और मानकीकृत इलेक्ट्रानिक शब्दावली (नमस्ते) पोर्टल और आयुष अनुसंधान पोर्टल जैसे अग्रणी डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से भारत न केवल अपने सदियों पुराने चिकित्सा ज्ञान की रक्षा कर रहा है, बल्कि व्यक्तिगत, साक्ष्य-आधारित और विश्व स्तर पर सुलभ स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार देने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।” आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश

कोटेचा ने कहा, “डब्ल्यूएचओ दस्तावेज में भारत की ओर से किए गए कई अग्रणी एआई-संचालित नवाचारों पर प्रकाश डाला गया है - जिसमें प्रकृति-आधारित मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके पूर्वानुमानित निदान से लेकर आयुर्वेद ज्ञान और आधुनिक जीनोमिक्स को एक साथ लाने वाली अभूतपूर्व आयुर्जेनोमिक्स परियोजना शामिल है। इस डिजिटल परिवर्तन का मूल आधार आयुष ग्रिड है। यह 2018 में शुरू किया गया एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म है जो कई नागरिक-केंद्रित पहलों जैसे कि एसएएचआई पोर्टल, नमस्ते पोर्टल और आयुष अनुसंधान पोर्टल की नींव का काम करता है। ये एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म न केवल भारत की पारंपरिक ज्ञान चिकित्सा प्रणालियों को संरक्षित और मान्य कर रहे हैं, बल्कि साक्ष्य-आधारित, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा ढाँचों के भीतर उनके वैश्विक एकीकरण को भी आगे बढ़ा रहे हैं।” विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह प्रकाशन न केवल वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा परिदृश्य में भारत के बढ़ते प्रभाव को मान्यता देता है, बल्कि एआई और आयुष क्षेत्र में कई प्रमुख भारतीय नवाचारों को भी मान्यता देता है। यह दस्तावेज आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी में एआई-संचालित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करता है, जिसमें निदान सहायता प्रणालियाँ भी शामिल हैं जो नाड़ी मापन, जीभ परीक्षण

और प्रकृति मूल्यांकन जैसी पारंपरिक विधियों को मशीनों के अनुप्रयोग और गहन तांत्रिका नेटवर्क के साथ एकीकृत करती हैं। ये प्रयास निदान सटीकता को बढ़ा रहे हैं और व्यक्तिगत निवारक देखभाल को सक्षम बना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संक्षिप्त विवरण में एक उल्लेखनीय विशेषता आयुर्जेनोमिक्स का उल्लेख है। यह वैज्ञानिक उपलब्धि जीनोमिक्स को आयुर्वेदिक सिद्धांतों के साथ जोड़ती है। इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेदिक संरचना प्रकारों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-आधारित विश्लेषण का उपयोग कर रोगों के पूर्वानुमानित संकेतों की पहचान करना और स्वास्थ्य संबंधी सुझावों को व्यक्तिगत बनाना है। यह दस्तावेज आधुनिक रोग स्थितियों में पुनर्प्रयोजन हेतु हर्बल विधियों के जीनोमिक और आणविक आधार को समझने के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है जो पारंपरिक ज्ञान को समकालीन विज्ञान के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल बनाने की भारत की पहल, जैसे पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल), को स्वदेशी चिकित्सा विरासत के संरक्षण और जिम्मेदारी से उपयोग के वैश्विक मॉडल के रूप में सराहा जाता है। इसके अलावा, प्राचीन ग्रंथों के सूचीकरण और अर्थ विश्लेषण के लिए एआई-संचालित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे समय-परीक्षित चिकित्सीय

ज्ञान तक आसान पहुँच संभव हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू औषधि की कार्यप्रणाली की पहचान, आयुर्वेद, पारंपरिक चीनी चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के बीच तुलनात्मक अध्ययन, और रस, गुण और वीर्य जैसे पारंपरिक मापदंडों का आकलन करने के लिए कृत्रिम रासायनिक संसर्गों के विकास हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग है। ये तकनीकी समाधान पारंपरिक औषधियों को मान्य और आधुनिक बनाने में मदद कर रहे हैं। दस्तावेज में ऑनलाइन परामर्श के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों को शामिल करने, आयुष चिकित्सकों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करने के लिए अंतर-प्रचालनीय प्रणालियों के विकास में भारत के व्यापक प्रयासों की भी सराहना की गई है। आयुष मंत्रालय इस मान्यता का स्वागत करता है और इसे पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक तंत्र बनाने में भारत के नेतृत्व का प्रमाण मानता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पारंपरिक चिकित्सा के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत परिकल्पित वैश्विक सहयोग और जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन ‘शल्यकॉन 2025’ का उद्घाटन किया

भारत और पड़ोसी देशों के विद्वानों, आयुर्वेदिक विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और छात्रों सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया

सूत्र/रे.स.ब्यू. सुश्रुत जयंती के मौके पर, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली में शल्य तंत्र पर आधारित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन, शल्यकॉन 2025 का उद्घाटन किया। एआईआईए के शल्य तंत्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुश्रुत संघ के सहयोग से आयोजित यह राष्ट्रीय सेमिनार, एनएसए के 25वें वार्षिक सम्मेलन का एक हिस्सा था। इस कार्यक्रम में भारत तथा नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी मुल्कों के विद्वानों, आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और शल्य चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और छात्रों समेत 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए श्री प्रतापराव जाधव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के मुताबिक, आयुर्वेद में अनुसंधान को और सशक्त करने की जरूरत बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “अनुसंधान को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। गहन वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल के जरिए, हमारी पारंपरिक प्रणालियों के प्रभाव को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा सकता है। भारत सरकार पहले ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों को 39 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं और 19 अतिरिक्त ऑपरेशन करने के लिए अधिकृत कर चुकी है, जिससे स्वास्थ्य सेवा के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण मजबूत हुआ है।” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपचार की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए शल्य चिकित्सा प्रोटोकॉल का मानकीकरण जरूरी है। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय के उप महानिदेशक श्री सत्यजीत पॉल, राष्ट्रीय सुश्रुत संघ के अध्यक्ष पद्मश्री प्रो. मनोरंजन साहू, एनएसए के सचिव प्रो. पी. हेमंत कुमार, निदेशक (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. (डॉ.) मंजूषा राजगोपाला भी उपस्थित थीं। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आयुर्वेद और प्रौद्योगिकी के जरिए नवाचार में भारत के सशक्त होते नेतृत्व पर जोर दिया। उन्होंने याद

दिलाया कि सितंबर 2024 में एआईआईए और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित एक वैश्विक तकनीकी बैठक में, पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक तकनीकी संक्षिप्त विवरण जारी किया गया था। आयुष भी, स्वदेशी चोटबॉट, एकीकृत आयुष मास्टर एप्लिकेशन और एएचएम- आईएस, आयुष ई-एलएमएस, आयुष अनुसंधान पोर्टल और नमस्ते योग ऐप जैसे 22 से अधिक डिजिटल मंचों जैसे उपायों के साथ एआई अनुप्रयोगों को आगे बढ़ा रहा है। भारत डबल्यूएचओ-आईटीयू एफजी-एआई4 एच पहल में भागीदारी के जरिए वैश्विक एआई शासन में भी योगदान दे रहा है। **कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:** कार्यक्रम के दौरान 13 और 14 जुलाई को लाइव सर्जिकल प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें 10 लेप्रोस्कोपिक/एंडोस्कोपिक प्रक्रियाएँ और 16 एनोरेक्टल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। इसके अलावा, शल्य तंत्र में मानकीकरण और नवाचार पर वैज्ञानिक सत्र, पोस्टर प्रस्तुतियों और विशेषज्ञ पैनल चर्चाएँ भी शामिल थे। आयोजन के अध्यक्ष, प्रो. (डॉ.) योगेश बडवे ने बताया कि एआईआईए अब रोजाना 2000 से अधिक रोगियों की सेवा करता है, और इसका शल्य तंत्र विभाग नियमित रूप से सामान्य, लेप्रोस्कोपिक, स्तन, एनोरेक्टल और मूत्र संबंधी सर्जरी करता है। ये विकास रोगी-केंद्रित एकीकृत देखभाल प्रदान करने में आयुर्वेद की प्रासंगिकता को दर्शाती है। “नवाचार, एकीकरण और प्रेरणा” विषय के साथ, शल्यकॉन 2025 आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ाएगा, जिससे एकीकृत स्वास्थ्य सेवा में भारत के नेतृत्व को बल मिलेगा। इस प्रतिष्ठित उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय सुश्रुत सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों के हाथों एक सम्मेलन स्मारिका पुस्तक का विमोचन भी किया गया और एक पीजी सारांश भी प्रस्तुत किया गया।

कोलकाता में 400 सीटों वाले स्नातक बालक छात्रावास का उद्घाटन

सूत्र/रे.स.ब्यू. आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री प्रतापराव जाधव ने राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान (एनआईएच), कोलकाता में स्नातक छात्रों के लिए 400 सीटों वाले यूजी बालक छात्रावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारत सरकार के शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल के पुरलिया से सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, श्री प्रतापराव जाधव ने कहा, “यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एनआईएच इस वर्ष अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। केवल 50 वर्ष पूरे करना एक गौरव की बात नहीं, यह सेवा, समर्पण और निरंतर उत्कृष्टता का उत्सव है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एनआईएच ने उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए सफल प्रयास किए हैं। श्री प्रतापराव जाधव ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के विस्तार को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएँ केवल बुनियादी ढाँचे का विस्तार नहीं हैं, बल्कि एनआईएच अपने मिशन में सशक्त हो सके इसके लिए ये स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान में एक समृद्ध वातावरण को बढ़ावा देने और बढ़ती शैक्षणिक और रोगी-देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों को दर्शाती हैं। उन्होंने निदेशक से परिसर में पूर्व छात्रों के लिए समर्पित एक कक्ष की व्यवस्था करने का आग्रह किया ताकि उनके समृद्ध अनुभव और विशेषज्ञता होम्योपैथी प्रणाली को और समृद्ध और सुदृढ़ बना सकें। एनआईएच के 51वें वर्ष में प्रवेश करते हुए, केंद्रीय आयुष मंत्री ने छात्रों, संकायों, पूर्व छात्रों और कर्मचारियों से बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और एक ऐसा संस्थान बनाने का आग्रह किया जो न केवल उपचार प्रदान करे बल्कि ज्ञान,

नवाचार और करुणा का भी मार्ग प्रशस्त करे। शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने अपने संबोधन में कहा कि यह संस्थान न केवल पश्चिम बंगाल का गौरव है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा में भारत की ज्ञान और उत्कृष्टता की समृद्ध परंपरा का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एनआईएच के छात्र देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह प्रधानमंत्री के “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के विजन को साकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनआईएच भारत को विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने मरीजों की महत्वपूर्ण संख्या पर प्रकाश डाला जो एनआईएच के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा कि यह संस्थान सस्ती, सुलभ और समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने एनआईएच के परिधीय ओपीडी की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि एनआईएच के डॉक्टरों ने कैंसर का भी इलाज किया है जो होम्योपैथी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। उन्होंने अंतःविषय दृष्टिकोण और मजबूत शोध की आवश्यकता पर बल दिया। उनकी आकांक्षा है कि एनआईएच अपनी उत्कृष्टता के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करे। एनआईएच के निदेशक ने अपने स्वागत भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ने प्रतिदिन लगभग 3,000 रोगियों की सेवा करने की उपलब्धि हासिल की है। निदेशक ने कहा, “यह केवल एक उद्घाटन नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से प्रतीक्षित स्वप्न का साकार होना भी है।” उन्होंने आशा व्यक्त की कि एनआईएच जल्द ही एक उत्कृष्टता केंद्र बनेगा जो हमारे अनुसंधान और चिकित्सा सेवाओं को और विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनआईएच केवल एक संस्थान नहीं है - यह एक भावना, एक परिवार, एक आंदोलन और सेवा का एक संकल्प है।

AI-Powered Future: Indian Railways and DFCCIL Seal MoU to Enhance Train Safety

Machine Vision Based Inspection System (MVIS) to Boost Train Safety, Reduce Manual Inspection and Prevent Service Disruptions



Source/RSB- In a significant step toward adopting cutting-edge technologies to improve service efficiency and automate the maintenance of rolling stock, Indian Railways has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) for the installation of Machine Vision Based Inspection System (MVIS) for monitoring the health of rolling stock. MVIS is a modern, AI/ML-based technology solution deployed on wayside that captures high-resolution images of the under-gear of moving trains and automatically detects any hanging, loose, or missing components. On detecting anomalies, the system generates real-time alerts to facilitate prompt response and preventive action. The MoU was formally signed by Shri Sumit Kumar, Director (Project & Development), Railway Board, and Shri Jawahar Lal, GGM (Mechanical), DFCCIL at Rail Bhawan, New Delhi, in the presence of Shri B. M. Agrawal, Member (Traction & Rolling Stock), Shri Praveen Kumar, Managing Director, DFCCIL, and senior officials from the Railway Board and DFCCIL. Under the terms of the MoU, DFCCIL will be responsible for the procurement, supply, installation, testing and commissioning of four MVIS units. This revolutionary system marks a first for Indian Railways. The technology is expected to significantly enhance the safety of train operations, reduce manual inspection efforts and help avoid potential accidents/service disruptions. This initiative also aligns with IR's broader objective of introducing modern, intelligent systems to the railway ecosystem. The signing of this MoU is poised to open new avenues for digital transformation in rail safety in building a future-ready rail infrastructure.

East Coast Railway Unveils Budget-Friendly Sleeping Pods at Visakhapatnam Station: A Smart Move for Passenger Comfort

Source/RSB- In a move aimed at enhancing passenger convenience, the East Coast Railway has launched budget-friendly sleeping pods at Visakhapatnam Railway Station. The facility includes 88 pod beds, with 18 beds reserved exclusively for women, ensuring safety and comfort for solo female travelers. These pods are equipped with modern amenities such as Wi-Fi, hot water, charging points, and personal lighting, offering a hotel-like experience within the station premises. A dedicated travel desk is also available to assist passengers with local guidance and bookings. The initiative is especially beneficial for travelers with overnight halts, delayed trains, or early-morning departures, offering them a safe and affordable resting space without leaving the station. With this launch, Visakhapatnam Station takes a step toward becoming a modern, commuter-friendly transport hub, reflecting Indian Railways' commitment to upgrading passenger services.

RITES Prepares DPR for Bhagadatta Flyover 2 in Assam

Source/RSB- RITES Ltd. takes pride in preparing the Detailed Project Report (DPR) for the recently completed Bhagadatta Flyover 2, a four-lane flyover built in just 9 months. This remarkable structure stands out as Assam's first flyover constructed using advanced composite structure technology. What makes it unique is the use of BUG girders embedded in RCC diaphragms at both ends, ensuring enhanced strength and durability. The Bhagadatta Flyover 2 is not only a symbol of engineering excellence but also a milestone in rapid infrastructure development in the region.

Central Railway's AC Local Task Force Elevates Travel Experience – 100% Complaints Attended

Source/RSB- Central Railway's Mumbai Division, in a bold and decisive move to elevate the travel experience while prioritizing the safety and comfort of passengers, undertook a unique initiative to curb irregular travel. On May 25th, 2024, CR introduced a dedicated AC Class Task Force to address issues related to irregular traveling in suburban trains. A specialised squad has been deployed to respond promptly to commuter concerns, aided by a dedicated 24/7 WhatsApp complaint number, 7208819987. This innovative approach allows passengers to report incidents of irregular travel, ensuring immediate assistance during travel hours and subsequent follow-ups as required. Response to every complaint received on the dedicated WhatsApp number is immediate. If the Special Squad is in the particular section mentioned in the complaint, they immediately swing into action. However, if the squad is not immediately available, then action is taken on the subsequent day. During the period 25th May 2024 to 30th June 2025, a total of 11,134 complaints were received and all were addressed within a short span of 2 days, marking a 100% resolution of complaints. This proactive

enforcement has led to a notable decline in complaints, with the daily average dropping significantly from 79 in June 2024 to 29 in June 2025. The maximum complaints received per day have also come down from 228 per day in June 2024 to 103 in June 2025. Based on a thorough analysis of complaints received, action taken, and deployment of special squads, an astonishing 1.22 lakh travellers were detected travelling without proper tickets in AC locals, and an amount of ₹4.01 crore was recovered as penalty during the period 25th May 2024 to 9th July 2025. This equates to an average of 365 passengers travelling without proper tickets daily and an average recovery of ₹1.19 lakh per day from offenders. This initiative has received widespread praise from passengers for Central Railway's proactive approach in upholding the high standards of its premium services. Notably, the Mumbai Suburban Network of Central Railway carries approximately 3.9 million passengers every day through its 1,810 services, including 80 AC local services daily, which carry approximately 78,000 passengers per day.

Vande Bharat Express Between Bengaluru and Shivamogga Coming Soon!

Source/RSB- Indian Railways is all set to introduce a new Vande Bharat Express connecting Bengaluru and Shivamogga, promising faster, more comfortable, and premium rail travel for passengers in Karnataka. This will be the 12th Vande Bharat train for the state, further strengthening its high-speed rail network and meeting the growing demand for better connectivity. The much-anticipated service is expected to benefit thousands of commuters, tourists, and business travelers, especially from the Shivamogga and Malnad regions, who have long awaited this direct high-speed link to the capital city. The news was shared by Bengaluru Central MP Sh. P.C. Mohan, who posted on X (formerly Twitter): "Shivamogga-Bengaluru Vande Bharat soon." Once operational, this train will drastically



reduce travel time while offering world-class amenities including modern seating, faster acceleration, onboard Wi-Fi, and superior safety features.

DMRC Inks MoU with Chennai Metro for 15-Year O&M Services

Source/RSB- An agreement was signed between Delhi Metro and Chennai Metro Rail Limited (CMRL) for Operation and Maintenance services for three corridors of Chennai Metro's Phase-II: Corridor-3 (Madhavaram Milk Colony to Siruseri SIPCOT-II Metro - Indigo Line), Corridor-4 (Lighthouse to Poonamallee Bypass - Orange Line) and Corridor-5 (Madhavaram Milk Colony to Sholinganallur - Red Line) including Maintenance Depots at Madhavaram, Poonamallee & Semmancheri. As per the agreement, DMRC will provide Operation and Maintenance services for a period of approximately 15 years. The contract awarded through international competitive bidding on 2nd April 2025 covers approximately 118km and 112 stations across Corridors 3, 4, and 5. Scope of work includes managing various Operations and

Maintenance Services which mainly include train operations, station management, depot functions and the Operational Control Centre, ensuring global-standards. The first section of Chennai Metro Rail Limited Phase-II is expected to be operational by December, 2025 and the entire Phase-II will be operational in a phased manner by December, 2028. This marks DMRC's second major O&M win under international bidding, following DMRC's successful bidding of Mumbai Metro Line-3 O&M Contract in 2023. The Delhi Metro is gradually expanding its footprint in the O&M services business across India by harnessing its more than two decade of O&M expertise. To further expand its presence across globe DMRC is also vying for O&M contracts around the world.

IRCON Achieves Milestone in Solar Energy with 75 MW Synchronization at Pavagada

Source/RSB- In a major step towards promoting sustainable green energy and aligning with the vision of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi to achieve net zero carbon emissions by 2030, Ircon Renewable Power Limited—a Special Purpose Vehicle (SPV) of IRCON—has successfully synchronized an additional 75 MW of solar power capacity at Pavagada, Karnataka. With this development, the total operational capacity of the solar power plant now stands at 300 MW, marking the successful completion of

the fifth phase of the planned 500 MW solar power project. Once fully completed, this project is set to be one of the major contributors to India's renewable energy goals. The initiative is expected to offset approximately 720 kilotonnes (KT) of carbon emissions annually, significantly contributing to environmental sustainability and the nation's clean energy transition. IRCON's continued progress in renewable infrastructure reflects its commitment to green development and supports India's larger climate objectives.

Railway Board Announces New General Managers for South Central and Western Railways

SHRI VIVEK KUMAR GUPTA TAKES OVER AS GENERAL MANAGER, WESTERN RAILWAY

Source/RSB- Shri Vivek Kumar Gupta, a senior officer of the Indian Railway Service of Engineers (IRSE) of the 1988 batch, has taken over the charge as General Manager of Western Railway on 11th July, 2025. Prior to his posting as General Manager, Western Railway he was working as the Managing Director of National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL), the organization entrusted with the execution of India's first Bullet Train Project. Shri Gupta has served as Principal Executive Director/Gati-Shakti at the Railway Board, Ministry of Railways, where he was responsible for the integrated functioning of seven (07) departments – Civil (Works, Project Monitoring & Station Development), Electrical (RE), Signal & Telecommunication, Traffic, Finance, Planning, and Economic Directorates – functioning as a cohesive unit for the planning and execution of all major railway projects including station development under the PM Gati-Shakti initiative. Shri Gupta has held several prestigious positions on Western and Central Railways, such as Chief Administrative Officer (Construction), Chief Track Engineer, Chief Bridge Engineer and Divisional Railway Manager (DRM). In these roles, he oversaw critical infrastructure works including new line construction, gauge conversion, doubling and multi-tracking projects, track construction works, traffic facilities and bridge maintenance. As Chief Engineer at Mumbai Railway Vikas Corporation (MRVC), Shri Gupta played a key role in coordination and



implementation of MUTP I, II & III projects, with a cumulative project value of around ₹20,000 Cr. He also led the preparatory work for the ₹34,000 Cr MUTP 3A project. His responsibilities involved extensive coordination with various agencies such as the World Bank, AIB, MMRDA, CIDCO and Government of Maharashtra on planning and execution matters. During his tenure as DRM of Bhusaval Division of Central Railway (April 2019 to August 2021), he ensured efficient operations with focus on safety, reliability, infrastructure improvement, staff welfare, customer satisfaction and expenditure control & revenue generation. Shri Gupta brings with him vast experience in railway operations, infrastructure management and project execution. He is well respected among officers and staff alike and there is strong confidence that under his visionary leadership, Western Railway will scale greater heights.

SHRI SANJAY KUMAR SRIVASTAVA HAS TAKEN OVER AS GENERAL MANAGER, SC RAILWAY

Source/RSB- Shri Sanjay Kumar Srivastava, Indian Railway Management Service (IRMS) has taken charge as General Manager, South Central Railway on 11th July, 2025. He belongs to the 1988 Batch of Indian Railway Engineering Service (IRSE). Prior to the posting he was holding the post of as General Manager, Central Organisation of Railway Electrification (CORE). He was instrumental in implementing various technological advancements and policies related to Civil Engineering. With an illustrious career spanning at RDSO, RITES, and the Railway Board, he has contributed significantly to railway infrastructure, metro projects, & advanced rail technologies, cementing his leadership credentials.



Innovations in Rail Technology at RDSO: Prior to this role, Shri Srivastava served as Principal Executive Director (Infra-1) at RDSO. During his tenure, he contributed to developing advanced rail technologies, including the 60kg R350HT grade rails, SRT/DRT with nine probes and B-Scan facilities, and Phased Array USFD for Flash Butt joints. His collaborations with M&C Directorate and Bhilai Steel Plant were pivotal.

Extensive Experience across Key Roles: Shri Srivastava began his career as Assistant Engineer, Valsad, and later held various critical positions such as Divisional Track Engineer and Dy. Chief Engineer in Mumbai and Vadodara. His tenure at RITES as General Manager (Urban Transport) saw his immense success contributions to metro projects, including

Kolkata, Kochi, and Nagpur metros, involving planning, design, & tendering processes.

Educational and Professional Accomplishments: An alumnus of IIT Roorkee and IIT Delhi, Shri Srivastava also holds an MBA from the University of Maryland, USA. With a career spanning roles across Indian Railways including as Divisional Railway Manager, Bikaner, he has a profound understanding of engineering, project management, & general administration. Shri Sanjay Kumar Srivastava's appointment as General Manager of South Central Railway underscores his extensive expertise in railway engineering, metro development, and administrative leadership. His contributions to technological innovation and infrastructure development will steer South Central Railway towards greater efficiency and

Additional Member (Traction), Railway Board, Conducted Inspection and Inaugurates CSR-backed Computer Centre in Guntakal Division



Source/RSB- Shri Vijay Pratap Singh, Additional Member (Traction), Railway Board, conducted a window trailing inspection between Guntakal and Gooty during his visit to the Guntakal Division. He was accompanied by Shri Chandra Shekhar Gupta, Divisional Railway Manager (DRM), Guntakal. The inspection primarily focused on reviewing the condition of tracks, Overhead Equipment (OHE), and other vital safety infrastructure. The objective was to assess operational efficiency, ensure adherence to safety standards, and identify areas for further enhancement of rail operations. As part of the visit, Shri Vijay Pratap Singh also inaugurated a newly established computer centre at the Zilla Parishad Girls High School, Gooty. The facility has been developed under a Corporate Social Responsibility

(CSR) initiative by M/s Wabtec Corporation, in collaboration with Indian Railways. This initiative aims to empower students, particularly girls, by providing access to digital literacy and foundational computer education. Addressing the students on the occasion, Shri Singh highlighted the pivotal role of education in nation-building and urged them to take full advantage of the resources provided. He inspired the young minds to develop a passion for learning and emphasized the transformative power of education in shaping their futures. This visit reflects Indian Railways' dual focus on operational excellence & community development, reinforcing its commitment to both infrastructural progress & social empowerment.



Northern Railway GM Conducts Review Meeting, Reiterates Firm Commitment to Safety

Source/RSB- Shri Ashok Kumar Verma, General Manager of Northern Railway, chaired a detailed review meeting at the Zonal Headquarters, Baroda House, with all Principal Heads of Departments. During the session, Shri Verma assessed the progress of various departmental works and highlighted Northern Railway's unwavering commitment towards operational safety. He stressed upon the importance of continuously strengthening safety measures and the need for their regular monitoring and evaluation. He further underlined that safety remains the topmost priority for Northern Railway and called upon all departments to work with coordination and diligence to uphold the highest standards of railway operations.



Indian Railways to Introduce Modern Reservation System by December 2025

Source/RSB- Indian Railways is set to launch a modernised reservation system by December 2025, offering passengers enhanced convenience and transparency. With the new system, travellers will be able to select their preferred berths, access dynamic fare calendars, and receive real-time waitlist updates. Designed to handle up to 1.5 lakh bookings per minute, the platform aims to significantly improve efficiency. Additionally, starting July 1, verified authentication will be mandatory for Tatkal bookings to enhance security and ensure a more transparent process.

Aizawl Joins Indian Rail Network After 26-Year Wait

The inauguration of the 51.38 km Bairabi– Sairang railway line in June has marked a historic moment, connecting Aizawl, the capital of Mizoram, to India's national rail network for the first time. Conceived in 1999 and with its foundation stone laid in 2014, the project faced immense engineering challenges. Chief Engineer Vinod Kumar highlighted the difficult hilly terrain, recurring landslides, and limited working seasons as key hurdles during construction. This long-awaited rail connectivity is expected to boost regional development by enhancing trade, improving accessibility, and reducing travel time. It will also facilitate easier movement of goods & passengers, strengthening economic integration with the rest of the country.